GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 62
ANSWERED ON 03.12.2021

FAME INDIA II SCHEME IN MAHARASHTRA

62* **DR. VIKAS MAHATME:**

Will the Minister of ***Heavy Industries*** be pleased to state:

(a) the status of implementation of the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid) Electric Vehicles in India (FAME India) II scheme in the State of Maharashtra regarding EV charging stations, city-wise details thereof;

(b) the current number of pending proposals with the Ministry, State-wise ; and

(c) whether Government has proposed a distance limit between which there must be at least one EV charging station, if so, details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES
(DR. MAHENDRA NATH PANDEY)

******

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT

Statement referred to in reply to parts (a) to (c) of Rajya Sabha Starred Question No. 62 for 03.12.2021 asked by Dr. Vikas Mahatme regarding "FAME India II scheme in Maharashtra".

(a): Sir, the Phase-II of Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME India) is being implemented for a period of 5 years w.e.f. 01st April, 2019 with a total budgetary support of Rs. 10,000 crores. Under Phase-II of FAME-India Scheme, Rs. 1000 Cr. is allocated for the development of charging infrastructure. This Ministry has sanctioned 2,877 Electric Vehicle Charging Stations in 68 cities across 25 States/UTs and 1576 charging stations across 9 Expressways and 16 Highways under Phase II of FAME India Scheme. The city-wise details of charging stations sanctioned under phase-II of FAME-India Scheme in respect of Maharashtra State are attached as **ANNEXURE**.

(b): Sir, there are no such pending proposal.

(c): As per the Ministry of Power guidelines, there must be at least one charging station at every 25 kms on both sides of the Highway and also at least one Charging Station for long Range/Heavy Duty EVs at every 100 kms on both sides of the Highway. For the city at least one charging station will be set up in a grid of 3km x 3km.

*****

ANNEXURE

City-wise details:

Maharashtra State		
Sl. No.	**City**	**Charging Stations**
1.	Mumbai	169
2.	Navi Mumbai	60
3.	Nashik	25
4.	Nagpur	38
5.	Thane	25
Total		**317**

Highways/ Expressway details:

Sl. No.	**Highways/ Expressways**	**Charging Stations**
1.	Mumbai – Pune Expressway	10
2.	Surat-Mumbai Expressway	30
3.	Mumbai – Delhi Highway	124
4.	Mumbai – Panaji Highway	60
5.	Mumbai – Nagpur Highway	70
6.	Mumbai – Bengaluru Highway	100
7.	Agra-Nagpur	80
8.	Kolkata- Nagpur	120
9.	Chennai- Nagpur	114
Total		**708**

*****

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 62

03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में फेम इंडिया-II योजना

***62. डा. विकास महात्मे:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईवी चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) II योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय के पास वर्तमान में राज्य-वार कुल कितने प्रस्ताव ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने दो ईवी स्टेशनों के बीच दूरी की कोई सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है ताकि निश्चित दूरी के अन्तराल कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय)

(क) से (ग): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

"महाराष्ट्र में फेम इंडिया-II योजना" के संबंध में राज्यसभा में 03.12.2021 को उत्तर के लिए नियत डा. विकास महात्मे के तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

(क) : महोदय, भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल,2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना विकास हेतु 1000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 68 नगरों के लिए 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तथा 9 एक्सप्रेसवे तथा 16 राजमार्गों के किनारे 1576 चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं। महाराष्ट्र राज्य के मामले में, फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों का नगर-वार ब्यौरा अनुलग्नक में है।

(ख): महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, राजमार्ग के दोनों ओर प्रति 25 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए और राजमार्ग के दोनों ओर प्रति 100 किलमीटर पर लंबी दूरी/हेवी ड्यूटी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। नगर के लिए 3 किलोमीटर x 3 किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

*****

अनुलग्नक

नगर-वार ब्यौरा:

महाराष्ट्र राज्य		
क्रम संख्या	**नगर**	**चार्जिंग स्टेशन**
1.	मुंबई	169
2.	नवी मुंबई	60
3.	नाशिक	25
4.	नागपुर	38
5.	ठाणे	25
कुल		317

राजमार्गों/एक्सप्रेसवे का ब्यौरा:

क्रम संख्या	**राजमार्ग/एक्सप्रेसवे**	**चार्जिंग स्टेशन**
1.	मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे	10
2.	सूरत-मुंबई एक्सप्रेसवे	30
3.	मुंबई-दिल्ली राजमार्ग	124
4.	मुंबई-पणजी राजमार्ग	60
5.	मुंबई-नागपुर राजमार्ग	70
6.	मुंबई-बेंगलूरु राजमार्ग	100
7.	आगरा-नागपुर	80
8.	कोलकाता-नागपुर	120
9.	चेन्नै-नागपुर	114
कुल		708

*****

श्री उपसभापति : पहली सप्लीमेंटरी।

DR. VIKAS MAHATME: Sir, I would like to congratulate the hon. Minister कि यह जो फेम इंडिया-II योजना है, इसकी वजह से वातावरण दूषित न हो और हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, वे कम हो जाएं, इसके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि लोग ये टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स तभी ज्यादा परचेज़ करेंगे, जब इनमें फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स होंगे। अभी तो इसमें काफी अधिक समय लगता है, इसलिए मेरा यह कहना है कि महाराष्ट्र में और सभी जगहों पर ज्यादा-से-ज्यादा फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें अभी डेढ़-दो घंटे से ज्यादा का समय लगता है। तो मेरा सवाल यह है की यह कैसे कार्यान्वित होगा, इसे लोगों के उपयोग के लिए कैसे आगे बढ़ाया जायेगा, नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन्स कैसे बढ़ाये जाएंगे, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : उपसभापति महोदय, माननीय सांसद जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फेम इंडिया-I और फेम इंडिया-II ये दोनों योजनाएं चार्जिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोत्साहन की स्कीम्स हैं, इन पर लगातार गंभीरता से विचार हुआ और हाल ही में मैंने हमारे विभाग से जुड़ी देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था, जो कि ऑटो field में शोध का काम करती है, एआरएआई पुणे, उसको इसके लिए हमारे मंत्रालय स्तर से निर्देश दिया है और वह फास्ट चार्जिंग के एक प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने फास्ट चार्जिंग पर अभी एक प्रोटो तैयार कर लिया है और मेरी कोशिश है कि वह अगले अक्टूबर-नवंबर तक फाइनल शेप में आ जाएगा और दिसंबर, 2022 तक हम उसे मार्केट में इंडस्ट्रीज़ के बीच और गवर्नमेंट्स के बीच प्रस्तुत कर देंगे। इस पर गंभीरता से काम हो रहा है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Second supplementary.

डा. विकास महात्मे : उपसभापति जी, हम जो भी manufacturing करने की कोशिश करते हैं, 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत वह भारत में ही हो, इसकी कोशिश रहती है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम बैटरी लगती है, वह हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो क्या यह बैटरी भारत देश में बनाई जायेगी? यदि हम इसे इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक-डेढ़ साल के बाद अगर यह बेकार हो जायेगी और हमें इसे थ्रो-ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरा यह सवाल है कि environment पर बिना pollution का इफेक्ट डाले हुए इसकी dismantling कैसे की जायेगी?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : उपसभापति महोदय, मैं माननीय सांसद और माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऑटो के field में पीएलआई-1 में 18,100 करोड़ रुपये की लिथियम बैटरी हिन्दुस्तान में ही बने, इस पर प्रक्रियायें शुरू कर दी गई हैं, आरएफटी फ्लोट हो गई है और उसके लिए बहुत गुड रिस्पॉंस देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आ रहा है। हम "आत्मनिर्भर भारत" के तहत बहुत तेजी से advanced chemical cell बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उस

पर हम उनको एक बहुत बड़ी सहायता राशि दे रहे हैं, जिसकी पूरी नीति आरएफटी के थ्रू देश के पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने इसके waste disposal की बात कही है, उस पर भी भारत सरकार माननीय मोदी जी की अगुवाई में बहुत ही सजग है और अभी सितम्बर, 2021 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन द्वारा एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, जो Battery Waste Management Rules, 2019 को finalise करेगी। इससे आगे इसका समाधान सुनिश्चित होगा।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I would like to ask a fundamental question. With threat of climate change looming large and our hon. Prime Minister's commitment at Glasgow Summit to bring down emissions to zero by 2070, it is unlikely to meet that goal with our currently planned action. So, we need to alter our policies on expenditure and direct our economic policies towards this goal.

Shifting to EVs is a step towards that. But, it needs increased allocations. So, my question is: Will the Government consider attaching charging stations mandatorily at every petrol pump? Obviously, this will
require more expenditure, space, time and money. So, will the hon. Minister take a fundamental step in this direction to shift the economic policies? And, will the Government think about setting up of a commission for climate change in the nation?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : उपसभापति महोदय, माननीय सांसद की चिंता और उनका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर भी बहुत गंभीरता से सजग है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'लाल किले' से ग्रीन एनर्जी को लेकर हाइड्रोजन मिशन की एक संकल्पना दी, इसके लिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से एनर्जी फील्ड में आत्मनिर्भरता बनाई है, उस आत्मनिर्भरता की दिशा में हम सब हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन एनर्जी मिशन और e-vehicle के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।

हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तथा अन्य concerning ministries, जो इससे जुड़ी हैं, जैसे विद्युत मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री - इन सबके साथ मिल कर इस पर काम हो रहा है और यह कोशिश हो रही है कि देश में कुल मिला करके लगभग 70 हज़ार से अधिक पेट्रोल पम्पों के पास जगहें हैं। उनमें से 22 हज़ार पेट्रोल पम्पों पर हम लोग एक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर सहजता और तेजी से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें, इस पर काम हो रहा है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, यह प्रश्न hybrid electric vehicles के बारे में है। प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र में मुम्बई, नवी मुम्बई, नासिक, नागपुर और थाणे में चार्जिंग स्टेशन की बात कही है। इसमें महाराष्ट्र का जो ग्रामीण भाग है, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या इन hybrid electric

vehicles को rural areas में भी ले जाने का कोई इरादा है या इनको सिर्फ शहरों तक ही सीमित रखने का इरादा है?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : उपसभापति महोदय, मैं माननीय महोदया को यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी इसकी जो प्राथमिकता तय की है, वह एक्सप्रेस-वे और हाईवे की है तथा सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की है, जहाँ पर ज्यादा प्रदूषण की स्थिति रहती है। इसके बाद इसको ग्रामीण एरियाज़ तथा हर जगह ले जाने की प्रक्रिया है और इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अभी इन तीन फील्ड्स में प्राथमिकता दी जा रही है।

MS. SUSHMITA DEV: Sir, I would like to know from the hon. Minister of Heavy Industries कि यह जो FAME की स्कीम है, उसके तहत आपने कहा कि आपने इसको करीब 68 सिटीज़ तथा 25 स्टेट्स एंड यूटीज़ में लागू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह स्कीम किसी नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट में है?
नॉर्थ-ईस्ट में हेवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री एक ही काम कर रही है और वह यह है कि असम में जो दो पेपर मिल्स हैं, वह उनको बंद कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ask supplementary only on the main question.

सुश्री सुष्मिता देव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर कोई नई इंडस्ट्री स्थापित की गई है, तो वे उसके बारे में बताएँ।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : उपसभापति महोदय, यह जो पेपर मिल की बात है, उस पर तो विषयांतर है।

श्री उपसभापति : जी, हाँ।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : महोदय, नॉर्थ-ईस्ट में चार्जिंग स्टेशंस बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस संबंध में हमारी जो नीति है, उसमें हम सभी को एक ओपन विंडो देते हैं और उन्हें इन्वाइट करते हैं। हम 70 परसेंट अपने द्वारा facilitate और 30 परसेंट, जो जैसे आता है, उस तरह से करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैंने नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक स्पेशल पहल की है और वहाँ भी इस पर तेजी से काम हो रहा है।